

आकाशवाणी गोरखपुर
प्रादेशिक समाचार

दिनांक—30 अगस्त 2024

7:20 AM

पहले मुख्य समाचार।

- उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के साठ हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिये चौथे और आखिरी चरण की परीक्षा आज से। प्रदेश के सभी एक हजार एक सौ चौहत्तर केन्द्रों पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में सात सौ पच्चीस करोड़ रुपये की तीन सौ बत्तीस विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। रोजगार मेले में एक हजार से अधिक युवाओं को वितरित किये नियुक्ति पत्र।
- राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को वितरित किये मेडल और प्रमाण पत्र। कहा— नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को तैयार करें युवा।
- मंकी पॉक्स से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट। जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर।

उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के 60 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिये चौथे और पांचवें चरण की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा के लिये 67 जिलों में कुल एक हजार 174 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। सुरक्षा और निगरानी की कड़ी व्यवस्था की गयी है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों की बैठक कर परीक्षा को नकलविहीन और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को कहा है। परीक्षा में हिस्सा लेने के लिये विभिन्न प्रदेशों से अभ्यर्थी एक दिन पहले ही परीक्षा केन्द्रों पर पहुंच गये। आज से दो पालियों में शुरू हो रही आखिरी चरण की यह परीक्षा कल सम्पन्न हो जाएगी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये रोडवेज बसों में एडमिट कार्ड दिखा कर निश्चल यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कानपुर में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार और ऋण मेले के अंतर्गत एक हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही पांच हजार सत्ताइस लाखार्थियों को एक सौ इक्यानवे करोड़ का ऋण भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने आठ हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए और सात सौ पच्चीस करोड़ की तीन सौ बत्तीस विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, आज वह देश का अग्रणी प्रदेश बन चुका है। कानपुर की लाल इमली मिल के पुनरुद्धार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़े पैकेज के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन रोजगार का लक्ष्य दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार दो वर्षों में दो लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देगी।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन रोजगार का लक्ष्य दिया है दो लाख सरकारी नौकरी देंगे और पचास लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, वन डिस्ट्रिक्वन प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के साध्यम से स्वतः रोजगार की योजना के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में छात्र-छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए। दीक्षांत समारोह में एक हजार चार सौ बासठ विद्यार्थियों को उपाधि और 19 टॉपर विद्यार्थियों को 42 पदक प्रदान किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ युवा अपने आप को तैयार करें। युवाओं को विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी उद्योग जगत में जाकर प्रशिक्षण की उम्मीद न करें। अध्ययन के दौरान ही खुद को इस तरह तैयार करें कि जिम्मेदारी मिलने के बाद पहले दिन से ही एक परिपक्व इंजीनियर के तौर पर अपनी सेवा सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने इसके लिये शिक्षकों को भी प्रेरित किया और विश्वविद्यालय में उद्योग की मांग के अनुरूप विद्यार्थियों को तैयार करने की सलाह दी।

राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय भारत सरकार के बजट का अध्ययन करें और योजना बनायें कि कैसे इसका उपयोग करना है। किस तरह रोजगार का सृजन किया जा सकता है, विश्वविद्यालय इसे लेकर व्यवस्थित ढंग से कार्य करे। वहीं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वरिष्ठ विज्ञानी एस. नम्बी नारायणन ने विद्यार्थियों को भारत को नासा के तर्ज पर एशियाई अंतरिक्ष एजेंसी बनाये जाने की पहल करने की सलाह दी। दो दिवसीय गोरखपुर के दौरे के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी।

लखनऊ के लोक भवन में आज आयोजित होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ष दो हजार तीन, दो हजार बारह, दो हजार पन्द्रह, दो हजार सत्रह और दो हजार बाइस की विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाओं तथा नीतियों के तहत बत्तीस निवेश इकाइयों को करीब तेरह सौ करोड़ रुपये का प्रोत्साहन लाभ राशि वितरित करेंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री दस हजार सात सौ पन्द्रह करोड़ रुपये के कुल अट्टाइस निवेश प्रस्तावों को लेटर ऑफ कर्मट के प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे।

प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलने के मामले में उत्तर प्रदेश, देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रदेश में नौ दशमलव चार छ: करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जन धन खाता खोले गए हैं, जो देश भर में खोले गए कुल खातों का 18 प्रतिशत है। इसमें भी लगभग पांच करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाताधारक महिलाएं हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन खाते के माध्यम से रूपे कार्ड वितरित करने में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना ने एक दिन पूर्व दस वर्ष पूरे किए हैं। इस समय अन्तराल में पूरे देश में अब तक तिरपन करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए गए हैं।

मंकी पॉक्स से बचाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एडवाइजरी जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। विभाग ने मंकी पॉक्स से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर – एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच चार पांच जारी किया है। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि सभी जिलों के एंट्री प्लाइंट्स पर मरीजों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गये हैं। उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश में संदिग्ध रोगियों की पहचान और उपचार के निर्देश दिए हैं।

नीति आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने के लिये कई सिफारिशों की है। आयोग ने तिलहन की खरीदारी हर हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने, खाद्य तेल के आयात पर शुल्क में वृद्धि और तिलहन के उत्पादन के लिये क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ ही तिलहन के बीज की उपलब्धता के लिये हर ब्लॉक में एक गांव को तिलहन के बीज वाले गांव के रूप में विकसित करने की सिफारिश की है। आयोग ने फूड इंडस्ट्रीज को घरेलू खाद्य तेल के इस्तेमाल पर इन्स्टीटिव देने के साथ ही तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये निजी सेक्टर के साथ सहभागिता की भी सिफारिश की है। भारत को अपनी जरूरत का सात प्रतिशत खाद्य तेल आयात करना पड़ता है। ऐसे में खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिये नीति आयोग की इस सिफारिश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण— यूपीसीडा ने पन्द्रह जिलों में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन और आठ जिलों में व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में चार सितंबर को आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जबकि मेंगा ई-निलामी तेरह सितंबर को ऑनलाइन होगी। प्रक्रिया के अंतर्गत जिन आठ जिलों में व्यावसायिक भूखण्ड के आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। उसमें अमेठी, बरेली, बाराबंकी, जालौन, मुरादाबाद, मथुरा और प्रयागराज प्रमुख हैं। वर्ही, व्यावसायिक भूखंडों की ई-निलामी अमेठी, अमरोहा, बांदा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, कानपुर देहात, मथुरा, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, संभल, शाहजहांपुर, उन्नाव, सहारनपुर और वाराणसी में भी होगी। इस मेंगा ई-निलामी के जरिये एक सौ सात औद्योगिक और व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन का मार्ग सुनिश्चित हो सकेगा।

प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए वित्तीय अनुदान की राशि को 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए कर दिया है। अनुदान राशि में वृद्धि से अब प्रदेश के दिव्यांगजनों को महंगे कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण भी किया जा सकेगा।

बहराइच में आतंक बने भेड़ियों के झुंड में से सबसे खूनखार भेड़िये को कल वन विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम ने पकड़ लिया। ऑपरेशन भेड़िया नाम से चलाए गए इस पूरे अभियान की निगरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा की। अब तक वन विभाग ने बहराइच क्षेत्र से चार भेड़ियों को पकड़ा है, जिनमें से एक को गोरखपुर चिड़ियाघर में स्थानांतरित किया गया है। दो अन्य भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक-वन्यजीव संजय श्रीवास्तव ने बताया कि कल सुबह भेड़िये के पैरों के निशान देखे गए और उसके बाद सिसैया गांव से भेड़िये को पकड़ा गया।
